



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2003/पौष 13, 1924

No. 5]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2003/PAUSA 13, 1924

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 3 जनवरी, 2003

प्रतिभूति संविदा ( विनियमन ) अधिनियम, 1956 की धारा 11 के अधीन भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध-परिषद् को अतिष्ठित करते हुए आदेश

का.आ. 5(अ).—1.0 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इसमें इसके पश्चात् "भाप्रविबो" के रूप में निर्दिष्ट) ने, अपने तारीख 28 सितंबर 2001 के आदेश द्वारा, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (इसमें इसके पश्चात् "प्रसंविअ" के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 6(3) के अधीन भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज (इसमें इसके पश्चात् "बीएचएसई" के रूप में निर्दिष्ट) के संबंध में एक्सचेंज के कतिपय सदस्यों द्वारा भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज सदस्य कल्याण न्यास (इसमें इसके पश्चात् "एमडब्ल्यूटी" के रूप में निर्दिष्ट) के माध्यम से 1.30 करोड़ रुपये तक की निधियों को एक्सचेंज के बाहर अपयोजित करने संबंधी कामकाज की जाँच संस्थित की। भाप्रविबो ने संसद के सदस्यों से और बीएचएसई के प्रबंध-परिषद् में भाप्रविबो के नामनिर्देशिती तथा अन्यो से इसे प्राप्त अभ्यावेदनों / शिकायतों के आधार पर उक्त जाँच संस्थित की।

2.0 जाँच अधिकारी ने तारीख 28 सितंबर 2001 के आदेश द्वारा, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 (इसमें इसके पश्चात् "प्रसंविनि" के रूप में निर्दिष्ट) के नियम 16 के उपबंधों के अनुसार जाँच की और 22 अक्टूबर 2001 को भाप्रविबो को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जाँच अधिकारी ने अपनी तारीख 22 अक्टूबर 2001 की उक्त रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ यह पाया है कि :-

- 1) बीएचएसई ने भाप्रविबो को एमडब्ल्यूटी की स्थापना संबंधी सूचना नहीं दी और इसकी स्थापना के लिए भाप्रविबो से अनुमति अभिप्राप्त नहीं की ।
- 2) एमडब्ल्यूटी से बीएचएसई द्वारा सदस्यों को संवितरित 95,83,782/- रुपये की कुल ऋण-राशि में से, रु.94,13,782/- अर्थात् लगभग 98%, बकाया और बीएचएसई के सदस्यों द्वारा संदेय है जो या तो बीएचएसई के पदाधिकारी या एमडब्ल्यूटी के न्यासी थे । ऋण-राशि का 95% सदस्यों के आवक-भुगतान (पे-इन) दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रदान किया गया था । श्री बाबूलाल शर्मा द्वारा उधार ली गई कुल रकम, कुल राशि का 92.5% होती है । निम्नलिखित सारणी ऋणों की बकाया स्थिति का वर्णन देती है :

क्र. सं.	सदस्य का नाम	बीएचएसई में स्थिति	एमडब्ल्यूटी में स्थिति	मूल ऋण राशि	ब्याज राशि	कुल
1.	अरुण कुमार गिरधर	अध्यक्ष सितंबर 1994 से सितंबर 1995		1,12,843	3,43,639	4,56,482
2.	अंजनी कुमार सिंह	कोषाध्यक्ष सितंबर 1999 से सितंबर 2001	न्यासी सितंबर 1996 से सितंबर 2001	2,74,620	1,98,810	4,73,430
3.	बाबूलाल शर्मा	उपाध्यक्ष सितंबर 1999 से सितंबर 2000	--	88,62,319	45,31,98	1,33,94,307
4.	धर्मेन्द्र पी सिंह	कोषाध्यक्ष सितंबर 1997 से सितंबर 1999	न्यासी सितंबर 1997 से सितंबर 2000	84,000	37,500	1,21,500
5.	जसवंत सिंह	--	--	10,000	1,505	11,505
6.	निर्मल बांका	--	न्यासी सितंबर 1996 से सितंबर 1997	80,000	8,312	88,312
7.	एस केदारस्वामी पात्रा	--	--	1,00,000	19,824	1,19,824
8.	संतोष कुमार झोंगन	--	--	60,000	11,994	71,994

	कुल			95,83,782	51,53,57	1,47,37,354
--	-----	--	--	-----------	----------	-------------

- 3) ऋण पूरी तरह से मौखिक चर्चा के आधार पर दिये गये थे और ऐसे ऋण जारी करने के लिए कोई विनिर्दिष्ट अध्यपेक्षा एमडब्ल्यूटी से बीएचएसई द्वारा प्राप्त नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, बीएचएसई से एमडब्ल्यूटी को ऋणों की मंजूरी हेतु किसी प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया था और एमडब्ल्यूटी द्वारा बीएचएसई को किसी अवसर पर यह उपदर्शित करते हुए कोई निर्देश नहीं किया गया था कि ऋण तथा ब्याज की चुकौती एक्सचेंज के सदस्यों में से किसी द्वारा नहीं की जा रही है।
- 4) प्रबंध-परिषद् ने 12 जुलाई 1997 को आयोजित अपनी बैठक में बीएचएसई से एमडब्ल्यूटी के प्रति कुल अंशदान पर रु.25.00 लाख की अधिकतम सीमा अधिरोपित की थी। प्रबंध-परिषद् को बीएचएसई से रु.25.00 लाख की अधिकतम सीमा से अधिक ऋण को मंजूर किये जाने के विषय में सूचित नहीं किया गया था और परिषद् को लेखापरीक्षक का संप्रेक्षण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् 1 सितंबर 2001 को ही बृहत् बकाया ऋण के बारे में पता चला।
- 5) एमडब्ल्यूटी का उपयोग बीएचएसई के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यतः उनके आवक-भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए किया गया है। एक्सचेंज के पदाधिकारी तथा एमडब्ल्यूटी के न्यासी एमडब्ल्यूटी द्वारा प्रदान किये गये ऋणों के प्रमुख हिताधिकारी हैं और कुछ मामलों में ऋण बिना समुचित जमानत के प्रदान किये गये थे।

3.0 उक्त जाँच रिपोर्ट में जाँच अधिकारी की सिफारिशों के आधार पर, भाप्रविबो ने प्रसंविनि के नियम 11 के अधीन इसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 29 जनवरी 2002 के पत्र द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को, निम्नलिखित कार्रवाईयाँ तुरंत करने का निदेश दिया :

1. कार्यपालक निदेशक के खिलाफ उसके अभिकथित व्यापारिक क्रियाकलापों की शिकायतों तथा सदस्य कल्याण न्यास से ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया की अननुपालना की सत्यवादिता की जांच करने के लिए गैर-निर्वाचित निदेशकों को मिलाकर समिति का गठन करना और निष्कर्ष प्रस्तुत करना ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
2. एमडब्ल्यूटी की संरचना में तुरंत परिवर्तन करना और यह सुनिश्चित करना कि बहुसंख्यक न्यासी गैर-निर्वाचित निदेशक होने चाहियें। एमडब्ल्यूटी को तब तक ऋण प्रदान करना बंद कर देना चाहिये जब तक न्यास का पुनर्गठन नहीं हो जाता।

3. यह सुनिश्चित करना कि सदस्य, जिनके सदस्य कल्याण न्यास निधि से ऋण बकाया हैं, जिनमें श्री बाबूलाल शर्मा, श्री अंजनी कुमार सिंह तथा श्री मनोज ठक्कर सम्मिलित हैं को एक्सचेंज के अथवा किसी अन्य खंड (सेगमेंट) जहाँ भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज दलाल के रूप में या सदस्य कल्याण न्यास के न्यासियों के रूप में कार्य कर रहा है में पदाधिकारियों के रूप में कार्य नहीं करना चाहिये ।
4. बकाया ऋण जिसमें ब्याज सम्मिलित है की वसूली हेतु तुरंत कानूनी कदम उठाना । एक्सचेंज तथा सदस्य कल्याण न्यास को सदस्यों जिनके ऋण बकाया हैं के खिलाफ दांडिक कार्यवाहियाँ शुरू करने पर भी विचार करना चाहिये ।
5. यह सुनिश्चित करना कि किसी सदस्य जिसके ऋण बकाया हैं को भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज में तथा अन्य खंडों जहाँ भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज की समनुषंगी दलाल के रूप में कार्य कर रही है में व्यापार करने की अनुमति नहीं है ।
6. सदस्यों से बकाया ऋण वापस प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना कि किसी सदस्य जिसके ऋण बकाया हैं को एक्सचेंज से कोई बीएमसी, नकदी/प्रतिभूति प्रत्याहृत करने की अनुमति नहीं होनी चाहिये ।
7. अब से, भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सदस्य कल्याण न्यास को समस्त ऋण केवल तभी प्रदान करना जब प्रबंध-परिषद् से अनुमोदन अभिप्राप्त कर लिया गया हो ।

3.1 यह और निदेश दिया गया था कि तारीख 29 जनवरी 2002 का पत्र एक्सचेंज के प्रबंध-परिषद् के समक्ष रखा जाये और यह कि उन्हें उक्त पत्र की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर भाप्रविबो को उत्तर देना चाहिये । एक्सचेंज ने तारीख 8 फरवरी 2002 के अपने पत्र द्वारा भाप्रविबो को सूचित किया कि मामला 16 फरवरी 2002 को आयोजित होने वाली प्रबंध-परिषद् की बैठक में रखा जा रहा है । तत्पश्चात्, एक्सचेंज ने तारीख 28 मार्च 2002 के अपने पत्र द्वारा सूचित किया कि 16 फरवरी 2002 को आयोजित होने वाली उक्त प्रस्तावित बैठक आयोजित नहीं हो सकी और परिषद् की बैठक 26 मार्च 2002 को हुई और इसमें निम्नलिखित विनिश्चय किये गये :-

(क) कार्यपालक निदेशकों के खिलाफ शिकायतों की जाँच करने के लिए निम्नलिखित लोक प्रतिनिधियों को मिलाकर एक समिति का गठन किया गया :

(i) श्री एम.एन. रे

- (ii) श्री जी.के. उपाध्याय
- (iii) श्री सैमसन महाराणा

- (ख) सदस्य कल्याण न्यास के न्यासी बोर्ड का पुनर्गठन सदस्यों द्वारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व के अभाव में नहीं किया जा सका ।
- (ग) निम्नलिखित सदस्य, सदस्य कल्याण न्यास को देय राशियों का भुगतान करने में विफल रहे :

- (i) श्री अंजनी कुमार सिंह
- (ii) श्री बाबूलाल शर्मा
- (iii) श्री अरुण कुमार गिरधर
- (iv) श्री एस. केदारस्वामी पात्रा
- (v) श्री धर्मेन्द्र प्रसाद सिंह

परिषद् ने एक्सचेंज के नियमों तथा उप-विधियों के अनुसार उपर्युक्त सदस्यों को निलंबन का नोटिस जारी करने का भी विनिश्चय किया ।

- (घ) परिषद् ने श्री थॉमस मैथ्यू को, सदस्य कल्याण न्यास द्वारा प्रदान किये गये ऋणों के हिताधिकारियों के खिलाफ दांडिक कार्यवाहियाँ शुरू करने की साध्यता की जाँच करने के लिए अधिवक्ता से परामर्श करने के लिए प्राधिकृत किया ।

3.2 भाप्रविबो ने तारीख 30 अप्रैल 2002 के अपने पत्र द्वारा तारीख 22 अक्टूबर 2001 की जाँच रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित की और बीएचएसई को निम्नलिखित सदस्यों के खिलाफ इसके नीचे यथा विनिर्दिष्ट कार्रवाई करने का निदेश दिया :

- (i) श्री अंजनी कुमार सिंह - 2 वर्षों हेतु निलंबन
- (ii) श्री बाबूलाल शर्मा - 2 वर्षों हेतु निलंबन
- (iii) श्री मनोज ठक्कर - 1 वर्ष हेतु निलंबन
- (iv) श्री धर्मेन्द्र प्रसाद सिंह - 1 वर्ष हेतु निलंबन

उन्हें उक्त सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निदेश दिया गया था और यह भी निदेश दिया गया था कि कारण बताओ नोटिसों में अधिरोपित की जाने वाली प्रस्तावित शास्ति का उल्लेख होना चाहिये और यह कि सदस्यों को वैयक्तिक सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये । स्टॉक एक्सचेंज को यह भी कहा गया था कि वैयक्तिक सुनवाई के

दृष्टिगत, यदि उनकी राय यह हो कि भाप्रविबो के निदेश को उपांतरित किया जाना आवश्यक है, तो वे यह मामला भाप्रविबो के पास उठा सकते हैं।

तारीख 29 जनवरी 2002 तथा 30 अप्रैल 2002 के पत्रों के प्रति बीएचएसई से कोई उत्तर आ नहीं रहा था और इसीलिये, कार्यपालक निदेशक तथा प्रबंध-परिषद् को संबोधित तारीख 5 अगस्त 2002 के पत्र द्वारा, भाप्रविबो ने उन्हें उक्त पत्रों में उल्लिखित निदेशों का पालन करने तथा पत्र की प्राप्ति की तारीख से 2 सप्ताहों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। उन्हें पत्र की प्राप्ति की तारीख से 2 सप्ताहों के भीतर कार्यपालक निदेशक के खिलाफ शिकायतों की जांच करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया। स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख 22 अगस्त 2002 के अपने पत्र द्वारा यह सूचित किया कि प्रबंध-परिषद् की बैठक तारीख 29 जनवरी 2002 तथा 30 अप्रैल 2002 के पत्रों में दिये गये निदेशों की अनुपालना करने संबंधी मामलों को उठाने के लिये 28 अगस्त 2002 को आयोजित की जायेगी।

- 4.0 यद्यपि उपर्युक्त मामला विचाराधीन था, भाप्रविबो को बीएचएसई के सदस्य श्री केदार स्वामी पात्रा तथा लोक प्रतिनिधि श्री एम.एन. रे से एक्सचेंज में वित्तसंबंधी कपट तथा अनियमितताओं के अभिकथन संबंधी शिकायतें प्राप्त हुईं। इसके अतिरिक्त, भाप्रविबो को समाचारपत्र की रिपोर्टों के माध्यम से यह पता चला कि एक्सचेंज के कतिपय सदस्यों को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था तथा कारावास की सजा सुनायी गई थी और यह कि स्टॉक एक्सचेंज में कई अनियमितताएँ हो रही थीं। उक्त शिकायत तथा मीडिया की रिपोर्टों के दृष्टिगत, भाप्रविबो ने 29 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2002 तक की कालावधि के दौरान बीएचएसई का निरीक्षण किया। निरीक्षण-दल ने निम्नलिखित संप्रेक्षण दिये :

- (i) बीएचएसई का कोई व्यापारावर्त (टर्नओवर) नहीं है : एक्सचेंज में अंतिम व्यापार 25 मई 2000 को हुआ था। एक्सचेंज की समनुषंगी अर्थात् भुवनेश्वर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज लि. का भी बीएसई में कोई व्यापार नहीं है और आईएसएस खंड में व्यापारावर्त नगण्य है। वर्तमान में, एक्सचेंज में केवल 68 कंपनियाँ सूचीबद्ध हैं, अंतिम सूचीबद्धकरण मई 2000 में हुआ। इस प्रकार, एक्सचेंज इक्विटी व्यापार हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की भूमिका अदा नहीं कर रहा है; दूसरी ओर, इक्विटियों में व्यापार बीएचएसई से एनएसई में अंतरित हो गया है और एनएसई के व्यापारिक टर्मिनल निवेशकों को इक्विटी व्यापार हेतु सुविधाएँ उपलब्ध करा रहे हैं जो कि मूलतः बीएचएसई द्वारा दी जा रही थीं।

- (ii) वर्ष 2000-01 के वार्षिक लेखा को अभी अंगीकृत किया जाना है और वर्ष 2001-02 के वार्षिक लेखा को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। वर्ष 2000-01 का वार्षिक लेखा 29 सितंबर 2001 को आयोजित वार्षिक साधारण अधिवेशन के समक्ष रखा गया था किंतु 1997-98, 1998-99, 1999-00 तथा 2000-01 वर्षों हेतु सदस्य कल्याण न्यास की लेखा-बहियों की लेखापरीक्षा कराने की सदस्यों की माँग की वजह से यह अंगीकृत नहीं हुआ था। कल्याण न्यास की लेखा बहियों की लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त लेखापरीक्षक ने एक्सचेंज को अपनी रिपोर्ट 12 जुलाई 2002 को प्रस्तुत की। रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात्, परिषद् ने कार्य की समीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षकों से अनुरोध करने का विनिश्चय किया।
- (iii) बीएचएसई का व्यय से आय का आधिक्य केवल रु. 29 लाख तक का था, जबकि, एक्सचेंज के पास नकदी तथा बैंक शेष के रूप में 4.94 करोड़ रुपये हैं जिनसे इसकी अधिकांश आय ब्याज के रूप में उत्पन्न होती है। इसलिये, यह प्रतीत होता है कि एक्सचेंज वर्तमान में जमाराशियों के माध्यम से उपार्जित ब्याज की आय पर ही बचा हुआ है।
- (iv) एक्सचेंज के विभिन्न कृत्यकारियों के बीच विरोध है। एक्सचेंज के कार्यपालक निदेशक तथा सचिव के प्रबंध-परिषद् के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं हैं और परिषद् के कई सदस्य कार्यपालक निदेशक तथा सचिव के खिलाफ कार्य करते हुए देखे गये हैं। एक्सचेंज के पदधारी एक्सचेंज के दैनंदिन कृत्यों हेतु पर्याप्त समय नहीं दे रहे हैं तथा पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में, हित के विरोध के दृष्टांत के रूप में, निरीक्षण के दौरान यह नोट किया गया कि प्रबंध-परिषद् ने 17 जुलाई 2002 को अपनी बैठक में लोक प्रतिनिधि श्री एम.एन. रे को कार्यपालक निदेशक तथा सचिव के खिलाफ उनके असंतोषजनक कार्यनिष्पादन, वृत्तिक अवचार, कर्तव्यों की अवहेलना तथा स्टॉक एक्सचेंज की निधियों के दुर्विनियोजन हेतु आरोपों का प्रारूप तैयार करने के लिए कहा था। तथापि, श्री रे ने प्रबंध-परिषद् को आरोपों का प्रारूप प्रस्तुत करने के बजाय कार्यपालक निदेशक तथा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जिसमें, उन्होंने स्वयं का वर्णन एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में किया।
- (v) कार्यपालक निदेशक के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए गठित समिति का गठन 26 मार्च 2002 को हुआ था और बाद में 17 जुलाई 2002 को इसमें 2 और सदस्य शामिल किये गये। हालांकि, समिति ने 3 बैठकें की हैं, फिर भी वे अपनी रिपोर्ट भाप्रविबो द्वारा यथा निदिष्ट 6 मास के भीतर प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। आज तक, समिति ने भाप्रविबो को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

- (vi) एमडब्ल्यूटी से ऋणों के संवितरण में अनियमितताओं के विषय में, यह देखने में आया था कि एमडब्ल्यूटी ने एनएसई के एक दलाल - मैसर्स इंडियन फाइनेंस गारंटी लि. (आईएफजीएल) को रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. के 16,200 शेयरों की सुपुर्दगी दी थी। ये शेयर 367/- रुपये प्रति शेयर की दर पर बेंचे गये थे। उक्त संव्यवहारों की आगमों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	उधारग्रहीता के नाम	शेयरों की संख्या	दर	रकम (रुपये)
1.	प्रदीप इंवस्टमेंट	5350	367	1963450
2.	कुमार एंड कं.	1900	367	697300
3.	ए.के. फाइनेंशियल एंड कं.	4600	367	1688200
4.	गिरधर एंड कं.	2000	367	734000
5.	डी.पी सिंह एंड कं.	2350	367	862450
	<b>कुल</b>	<b>16200</b>		<b>5945400</b>

बीएचएसई ने 59,45,400 की कुल बिक्री आगमों में से केवल 46,60,624 रुपये ही प्राप्त किये और 12,84,776 रुपये की रकम आईएफजीएल से देय है। तथापि, बीएचएसई के पास इन शेयरों की बिक्री से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं हैं और रिकॉर्ड की छानबीन करने पर कोई संविदा नोट (कॉन्ट्रैक्ट नोट) नहीं पाये गये थे।

- (vii) 10 लाख रुपये का गृह निर्माण अग्रिम सचिव तथा कार्यपालक निदेशक को मंजूर किया गया है। तथापि, उक्त ऋणों को संपत्तियों की बंधक द्वारा प्रतिभूत नहीं किया गया है। उपर्युक्त के अलावा, ऋण की संपूर्ण रकम सचिव को गृह-निर्माण के पूर्व ही संवितरित कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, सचिव ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से भी आवास-ऋण हेतु आवेदन किया जिसने कार्यपालक निदेशक से सचिव के आवास-ऋण को बैंक में अंतरित करने का अनुरोध किया था।



(viii) एक्सचेंज के कई पदाधिकारियों जिनमें प्रबंध-परिषद् के कतिपय सदस्य सम्मिलित हैं ने यह अभिकथन किया है कि लोक प्रतिनिधि श्री एम.एन. रे ने अपने प्राधिकार का अतिलंघन किया है। इस संबंध में, निरीक्षण-दल के संप्रेक्षण निम्नलिखित थे :-

(क) श्री एम.एन. रे ने एक्सचेंज के कार्यपालक निदेशक को, मुंबई तथा नई दिल्ली जाने हेतु प्रस्तावित दौरों हेतु हवाई उड़ान की टिकटें बुक कराने के लिए 70,000/- रुपये की रकम निर्मोचित करने के लिए पत्र लिखा था। तथापि, प्रबंध-परिषद् ने यह राशि निर्मोचित नहीं की।

(ख) प्रबंध-परिषद् ने श्री एम.एन. रे को स्टॉक एक्सचेंज के कार्यपालक निदेशक तथा सचिव के खिलाफ आरोपों का प्रारूप तैयार करने के लिए कहा था किंतु श्री रे ने प्रबंध-परिषद् को आरोपों का प्रारूप प्रस्तुत करने के बजाय कार्यपालक निदेशक तथा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। उक्त कारण बताओ नोटिस में, उन्होंने एक्सचेंज के अध्यक्ष के पदनाम का भी प्रयोग किया।

(ग) श्री रे ने कार्यपालक निदेशक को, जानकारी यथा एक्सचेंज के सितंबर 2001 से लेकर फरवरी 2002 तक के नकदी प्रवाह विवरण और ऐसी अन्य जानकारी मंगाते हुए पत्र जारी किये थे।

(ix) एक्सचेंज के लिए एक नये भवन का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इसके लिए जमीन पहले ही अर्जित की जा चुकी है और एक्सचेंज ने निर्माण के समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु एक भवन-समिति का गठन किया है। उक्त समिति ने तारीख 11 जून 2002 की अपनी बैठक में नये भवन हेतु 60 लाख रुपये के खर्च के अनुमोदन के लिए प्रबंध-परिषद् के समक्ष प्रस्ताव रखा। नये भवन में अधिक निवेश से एक्सचेंज के नकदी तथा बैंक शेष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और जिससे ब्याज की आय काफी कम हो सकती है। इस पर कि एक्सचेंज अभी बचा हुआ है।

5.0 भाप्रविबो के निदेशों का पालन करने में बीएचएसई की असफलता के मद्देनजर और निरीक्षण-दल द्वारा किये गये संप्रेक्षणों के दृष्टिगत, यह प्रतीत हुआ कि एक्सचेंज का प्रबंध-परिषद् अपने कर्तव्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में विफल रहा है और इसीलिये, भाप्रविबो ने उन्हें यह कारण बताने के लिए तारीख 24 सितंबर 2002 को कारण बताओ

नोटिस जारी किया था कि समुचित कार्रवाई जिसमें अधिक्रमण सम्मिलित है उनके खिलाफ क्यों नहीं की जानी चाहिये।

5.1 बीएचएसई के प्रबंध-परिषद् ने तारीख 8 अक्टूबर 2002 के पत्र द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने उत्तर में निम्नानुसार कथन किया है :-

- (i) कार्यपालक निदेशक के खिलाफ शिकायतों की जांच करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसे प्रबंध-परिषद् का अनुमोदन मिलने के पश्चात् भाप्रविबो को अग्रेषित कर दिया जायेगा।
- (ii) सदस्य कल्याण न्यास की संरचना में यथायोग्य संशोधन कर दिया गया है और वर्तमान में पाँच न्यासी हैं जिनमें से तीन गैर-निर्वाचित निदेशक हैं। न्यास ने भी दिसंबर 2001 से एक्सचेंज के सदस्यों को ऋण प्रदान करना बंद कर दिया है।
- (iii) सदस्य, जिनके सदस्य कल्याण न्यास से ऋण बकाया है, जिनमें श्री बाबूलाल शर्मा, श्री अंजनी कुमार सिंह तथा श्री मनोज ठक्कर सम्मिलित हैं, अब एक्सचेंज के पदाधिकारी नहीं रहे हैं, और न ही वे किसी भी खंड, जहां एक्सचेंज दलाल के रूप में कार्य कर रहा है, में किसी पद पर हैं।
- (iv) कुछ सदस्यों, जिन्होंने सदस्य कल्याण न्यास से ऋण लिया हुआ है, पर निम्नलिखित शास्तियाँ अधिरोपित की गई हैं।
  1. श्री बाबूलाल शर्मा - एक्सचेंज से निष्कासित
  2. श्री अंजनी कुमार सिंह - एक्सचेंज से निष्कासित
  3. श्री एस. केदारस्वामी पात्रा - सदस्यता के अधिकारों से निलंबित
  4. श्री धर्मेन्द्र पी. सिंह - मामला न्यायाधीन है
- (v) बकाया ऋणों की वसूली के लिए आवश्यक कानूनी कदम उठाये गये हैं और पाँच व्यक्तियों जिनमें स्टॉक एक्सचेंज के तत्कालीन कार्यपालक निदेशक तथा सचिव सम्मिलित हैं को वित्तसंबंधी अनियमितताओं हेतु राज्य की पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है।
- (vi) सदस्यों जिनके ऋण बकाया हैं को एक्सचेंज के किसी भी खंड में व्यापार करने से वर्जित कर दिया गया है।

- (vii) प्रबंध-परिषद् ने 1 मार्च 2002 को आयोजित अपनी बैठक में बीएमसी तथा प्रतिभूति निक्षेप को प्रत्याहृत करने और बकाया देयराशि के प्रति इसे समायोजित करने की अनुमति न देने का विनिश्चय किया था। प्रबंध-परिषद् ने सदस्य कल्याण न्यास को ऋण प्रदान करना बंद कर देने का भी विनिश्चय किया है।
- (viii) व्यापारावर्त के अभाव के विषय में, परिषद् ने यह निवेदन किया कि व्यापार का स्वरूप, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप से, चक्रीय बन गया है और उनका व्यापार के परिमाण पर कोई नियंत्रण नहीं है और इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि यह अधिक्रमण का आधार है।
- (ix) वर्ष 2000-01 के वार्षिक लेखा के विषय में, परिषद् ने यह निवेदन किया कि इसे इस तथ्य की वजह से अंगीकृत नहीं किया जा सका कि एमडब्ल्यूटी सदस्य कल्याण न्यास के खातों में अंतर्निहित अनियमितताएँ थीं। 1997-98, 1998-99 तथा 1999-00 और 2000-01 वर्षों हेतु एमडब्ल्यूटी के लेखों को प्रबंध-परिषद् द्वारा तारीख 1 अक्टूबर 2002 को आयोजित इसकी बैठक में स्वीकृत कर लिया गया है और इसे 9 नवंबर 2002 को आयोजित होनेवाले वार्षिक साधारण अधिवेशन में रखा जा रहा है। एक्सचेंज के वर्ष 2000-01 के लेखों के अंगीकरण के पश्चात्, वर्ष 2001-02 का लेखा परिषद् के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जायेगा।
- (x) एक्सचेंज के कृत्यकारियों के बीच जो विरोध था - वह एक्सचेंज के पदाधिकारियों तथा अधिकारियों द्वारा एक्सचेंज की निधियों के अपयोजन / के अपयोजन को दुष्प्रेरित करने के फलस्वरूप था। कार्यपालक निदेशक तथा सचिव को गिरफ्तार किये जाने और तत्पश्चात् निलंबित किये जाने के फलस्वरूप, यह विरोध समाप्त हो गया है।
- (xi) आईएफजीएल के पक्ष में प्रतिभूतियों की बिक्री की बाबत, परिषद् सिविल एवं दांडिक दोनों कार्रवाईयाँ शुरू कर रहा है।
- (xii) आवास-ऋण के विषय में, श्री संजय महापात्रा - सचिव (निलंबनाधीन) ने अपने आवास-ऋण की चुकौती कर दी है और एक्सचेंज श्री जय सदानि - कार्यपालक निदेशक (निलंबनाधीन) द्वारा लिये गए आवास-ऋण की वसूली के लिए कानूनी कदम उठाने पर विचार कर रहा है।

- 5.2 उपर्युक्त के मद्देनजर, प्रबंध-परिषद् ने भाप्रविबो से कोई कार्रवाई जिसमें प्रबंध-परिषद् का अधिक्रमण सम्मिलित है न करने का अनुरोध किया। स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध-परिषद् के अनुरोध के अनुसार, उन्हें 20 नवंबर 2002 को अध्यक्ष के समक्ष सुने जाने का अवसर प्रदान किया गया था। सुनवाई के दौरान, बीएचएसई के प्रबंध-परिषद् का प्रतिनिधित्व मैसर्स एल.एन. पटनायक, एस.के. झींगन तथा एम.एन. रे - समस्त बीएचएसई के निदेशक, द्वारा किया गया था। श्री एम.एन. रे परिषद् में लोक प्रतिनिधि भी हैं। सुनवाई के दौरान, एक्सचेंज के निदेशकों ने यह निवेदन किया कि उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में हुई अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को जिम्मेदार ओहदों से अपवर्जित करने हेतु प्रभावी कदम उठाये हैं और उनमें से कुछ को राज्य की पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें स्टॉक एक्सचेंज के सुप्रबंधन का एक और अवसर दिया जाये। उन्होंने पिछले प्रबंध-परिषद् के दुराचारों का भी संदर्भ दिया और यह कथन किया कि वे बीएचएसई में हुई अनियमितताओं हेतु जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कुछ और समय चाहते हैं।
- 6.0 मैंने मामले के तथ्यों, बीएचएसई के प्रबंध-परिषद् द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तर तथा मेरे समक्ष वैयक्तिक सुनवाई के दौरान उनके प्रतिनिधियों द्वारा किये गये निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है।
- 7.0 मैं यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि बीएचएसई प्रसंविनि के नियम 11 के अधीन जारी तथा तारीख 29 जनवरी 2002, 30 अप्रैल 2002 के पत्रों द्वारा संसूचित भाप्रविबो के निदेशों को कार्यान्वित करने में असफल रहा है। कार्यपालक निदेशक के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए प्रबंध-परिषद् द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट अभी भाप्रविबो को प्रस्तुत की जाना है, जबकि भाप्रविबो के तारीख 5 अगस्त 2002 के पत्र में यह नियत किया गया था कि इसे उक्त पत्र की प्राप्ति की तारीख से 2 सप्ताहों के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये।
- 7.1 मैं यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज के विभिन्न कृत्यकारियों के बीच विरोध अभी भी विद्यमान है और प्रबंध-परिषद् ने विश्वसनीयता को पुनःप्राप्त नहीं किया है। स्टॉक एक्सचेंज के कार्यपालक निदेशक तथा सचिव को राज्य की पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और परिणामस्वरूप स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निलंबित कर दिया गया है। उन्हें प्रतिस्थापित करने के लिए, प्रबंध-परिषद् ने श्री भाग्यधर बहेरा को सचिव के रूप में नियुक्त किया है और, अध्यक्ष तथा दो लोक प्रतिनिधियों से गठित उप-समिति के पर्यवेक्षण के अधीन, मैसर्स गदाधर मिश्रा तथा तपन रंजन - सहायक प्रबंधकों को एक्सचेंज के दैनंदिन कामकाज के संचालन का कार्यभार सौंपा है। भाप्रविबो को एक्सचेंज के सदस्यों से तथा उप-समिति के लोक प्रतिनिधियों में से एक श्री एम.एन. रे की ओर से भी सचिव श्री भाग्यधर

बहेरा के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। भाप्रविबो की जानकारी में यह भी लाया गया है कि माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय ने श्री एम.एन. रे के खिलाफ कठोर अवक्षेप पारित किये हैं। इसलिये, यह नहीं कहा जा सकता कि स्टॉक एक्सचेंज के कृत्यकारियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध कायम हो गये हैं और प्रबंध-परिषद् के सदस्यों की विश्वसनीयता कायम हो गयी है।

7.2 मैं यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 हेतु लेखों अंगीकृत करने में असफल रहा है। लेखों को अंगीकृत करने की असफलता वित्तीय कुप्रबंधन को उपदर्शित करती है। इस संबंध में एक्सचेंज द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, कि लेखों को 9 नवंबर 2002 को आयोजित होनेवाले वार्षिक साधारण अधिवेशन में अंगीकृत कर लिया जायेगा, को कार्रवाई द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है क्योंकि इस संबंध में कोई विवरण भाप्रविबो को अग्रेषित नहीं किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2001-02 के लेखों को अभी अंगीकृत किया जाना है।

7.3 मैं यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि मैसर्स इंडियन फाइनेंस गारंटी लि. को किये गये भुगतानों में हुई अनियमितताओं के विषय में प्रबंध-परिषद् द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये हैं। परिषद् का स्पष्टीकरण, कि कमी को पूरा करने के लिए यह मामला आईएफजीएल के पास उठाया गया है और यह कि परिषद् सिविल तथा दांडिक दोनों कार्रवाईयों कर रहा है, समाधानप्रद नहीं है। वर्ष 1999 में अनियमितताएँ देखी गई थीं और इनका उल्लेख 22 अक्टूबर 2001 को प्रस्तुत जाँच अधिकारी की रिपोर्ट में भी किया गया था। हालांकि, बीएचएसई को इस संबंध में अभी कोई प्रभावी कार्रवाई करनी है।

7.4 मैं यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि सुनवाई के दौरान, प्रतिनिधियों द्वारा किये गये निवेदनों से यह उपदर्शित हुआ कि वे केवल अपने पूर्वाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के इच्छुक थे और यह कि उनका रुझान भाप्रविबो के निदेशों का अनुसरण करने के प्रति नहीं था। अपितु, मेरे समक्ष हाजिर प्रतिनिधियों में से दो प्रतिनिधियों में विश्वसनीयता की कमी पायी गई थी। जैसा कि इसमें इसके ऊपर उल्लिखित है, जाँच अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा के उच्च न्यायालय द्वारा श्री एम.एन. रे के खिलाफ अवक्षेप पारित किये गये हैं और श्री एस.के. झींगन एमडब्ल्यूटी से लिये गये ऋण की बाबत व्यतिक्रमियों में से एक हैं।

8.0 उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनज़र, मुझे विश्वास है कि भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज का प्रबंध-परिषद् समुचित शासन और प्रसंविअ के उपबंधों तथा भाप्रविबो के निदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में और एक्सचेंज की कार्यप्रणाली में वित्तसंबंधी समुचित सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने में असफल रहा है। इसके परिणामस्वरूप, एक्सचेंज की कार्यप्रणाली में निवेशकों का विश्वास हासित हुआ है।

- 9.0 भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध-परिषद् को यह कारण बताने का सम्यक अवसर दिया गया था कि इसे अतिष्ठित क्यों नहीं किया जाना चाहिये । प्रबंध-परिषद् द्वारा दिया गया उत्तर समाधानप्रद नहीं पाया गया है । इसलिये, मेरी राय यह है कि यह अनिवार्य है कि बाजार की सुरक्षा तथा सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के लिए और स्टॉक एक्सचेंज की कार्यप्रणाली में निवेशकों के विश्वास को कायम रखने के लिए तुरंत उपाय किये जायें ।
- 10.0 भाप्रविबो यह सुनिश्चित करने के लिए आदेशाधीन है कि बाजार की सुरक्षा तथा सत्यनिष्ठा को संरक्षित करने के लिए और निवेशकों के हित को संरक्षित करने के लिए प्रभावी उपाय किये जाते हैं । इसलिये, यह आवश्यक है कि उन व्यक्तियों को एक्सचेंज के शासन से अपवर्जित किये जाने की आवश्यकता है जो प्रभावी कार्रवाई करने में असफल रहे हैं और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष व्यक्ति नियुक्त हो ।
- 11.0 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और भारत सरकार की तारीख 30 जुलाई 1993 की अधिसूचना सं. एस.ओ.573 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 11 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 4(3) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध-परिषद् को एतद्द्वारा 3 जनवरी 2003 से एक वर्ष की कालावधि के लिए अतिष्ठित करता हूँ और प्रबंध-परिषद् की समस्त शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रयोग करने तथा पालन करने के लिए श्री जय प्रकाश वर्मा को प्रशासक के तौर पर नियुक्त करता हूँ । श्री जय प्रकाश वर्मा ऐसे व्यक्तियों की सहायता ले सकेंगे जो वे प्रशासक के तौर पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आवश्यक समझें ।

[फाइल सं. भाप्रविबो/विधि/23/03]

ज्ञानेन्द्र नाथ बाजपेयी, अध्यक्ष

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA****NOTIFICATION**

Mumbai, the 3rd January, 2003

**Order under Section 11 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 superseding the Council of Management of Bhubaneshwar Stock Exchange**

**S.O. 5(E).—1.0** The Securities and Exchange Board of India (hereinafter referred to as “SEBI”), vide its order dated September 28, 2001, instituted an inquiry under Section 6 (3) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (hereinafter referred to as “SCRA”) into the affairs in relation to the Bhubaneshwar Stock Exchange (hereinafter referred to as “BhSE”) in relation to the siphoning of the funds out of the exchange to the tune of Rs.1.30 Crores through the Bhubaneshwar Stock Exchange Members Welfare Trust (hereinafter referred to as “MWT”) by certain members of the exchange. SEBI initiated the said inquiry based on representations/complaints received by it from Members of Parliament and from the SEBI Nominee on the Council of Management of BhSE and other quarters.

2.0 The Inquiry Officer appointed vide the order dated September 28, 2001, conducted inquiry as per the provisions of Rule 16 of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 (hereinafter referred to as “SCRR”) and submitted his report to SEBI on October 22, 2001. The Inquiry Officer in his said report dated October 22, 2001 has inter alia found that:-

- 1) BhSE did not intimate SEBI regarding setting up the MWT and did not obtain permission from SEBI to set up the same.

- 2) Out of the total loan amount of Rs.95,83,782/- disbursed to members by BhSE from the MWT, Rs.94,13,782 i.e. around 98%, are outstanding and payable by members of BhSE who were either office bearers of BhSE or Trustees of the MWT. 95% of the loan amounts were granted to meet the pay-in liabilities of members. The total amount owed by Shri Babulal Sharma constitutes 92.5% of the total loan amount. The following table describes the outstanding position of the loans:

Sl.No.	Name of member	Position in BhSE	Position in MWT	Principal loan amount	Interest Amount	Total
1.	Arun Kumar Girdhar	President Sep.1994 to Sep. 1995	--	1,12,843	3,43,639	4,56,482
2.	Anjani Kumar Singh	Treasurer Sep.1999 to Sep. 2001	Trustee Sep. 1996 to Sep. 2001	2,74,620	1,98,810	4,73,430
3.	Babulal Sharma	Vice-president Sep.1999 to Sep. 2000	--	88,62,319	45,31,98	1,33,94,307
4.	Dharmendra P Singh	Treasurer Sep.1997 to Sep. 1999	Trustee Sep. 1997 to Sep. 2000	84,000	37,500	1,21,500
5.	Jaswant Singh	--	--	10,000	1,505	11,505
6.	Nirmala Banka	--	Trustee Sep. 1996 to Sep. 1997	80,000	8,312	88,312
7.	S Kedarswamy	--	--	1,00,000	19,824	1,19,824



	Patra					
8.	Santosh Kumar Jhingan	--	--	60,000	11,994	71,994
	<b>TOTAL</b>			<b>95,83,782</b>	<b>51,53,57</b>	<b>1,47,37,354</b>

- 3) The loans were given purely on the basis of verbal discussions and no specific requisition for issuing such loans were obtained from MWT by BHSE. Further, no procedures were followed for sanctioning the loans from BhSE to MWT and no reference was made by the MWT to BhSE on any occasion indicating that the loans and the interest are not being repaid by any of the members of the exchange.
- 4) The Council of Management in its meeting held on July 12, 1997 had imposed a ceiling of Rs.25.00 Lakhs on the total contribution from BhSE to MWT. The Council of Management was not informed with regard to the sanctioning of loan from BhSE beyond the ceiling of Rs.25.00 Lakhs and the Council came to know of the huge outstanding loans only on September 1, 2001 after receiving an auditor's observation letter.
- 5) The MWT has been used by the Office Bearers of BhSE mainly to meet their pay-in liabilities. The Office bearers of the exchange and the trustees of the MWT are the major beneficiaries of the loans granted by the MWT and in some cases the loans were granted without proper security.

3.0 Based on the recommendations of the Inquiry Officer in the said inquiry report, SEBI in exercise of powers conferred on it under Rule 11 of the SCRR, directed the stock exchange vide letter dated January 29, 2002, to take the following actions immediately:

1961/03-3

1. To form a committee consisting of the non elected directors to enquire into the veracity of the complaints against the Executive Director of his alleged trading activities and non compliance with procedures in granting loans from the Members Welfare Trust and to submit the findings so as to take action against him.
2. To immediately change the constitution of MWT and to ensure that the majority trustees should be non-elected directors. The MWT should stop grant of loan till the trust is reconstituted.
3. To ensure that members having outstanding loans from the Member's Welfare Trust Fund including Shri Babulal Sharma, Shri Anjani Kumar Singh and Shri Manoj Thacker) should not act as office bearers of the exchange or in any other segment where Bhubhaneshwar Stock Exchange is acting as a broker or as trustees of the Members Welfare Trust.
4. To take immediate legal steps for recovering the outstanding loan including interest. The Exchange and the Members Welfare Trust should also consider initiating criminal proceedings against the members having the outstanding loans.
5. To ensure that no member having outstanding loans is allowed to trade in Bhubhaneshwar Stock Exchange and in other segments where the subsidiary of Bhubhaneshwar Stock Exchange is acting as a broker.
6. To get back outstanding loans from members and to ensure that no member having outstanding loans should be allowed to withdraw any BMC, Cash/security from the exchange.
7. Henceforth, to grant all loans by Bhubhaneshwar Stock Exchange to Members Welfare Trust only after approval has been obtained from the council of management.

3.1 It was further directed that the letter dated January 29, 2002 be placed before the council of management of the exchange and that they should reply to SEBI within 7 days of receipt of the said letter. The exchange vide their letter dated February 8, 2002 informed SEBI that the matter is being put up to the meeting of the council of management to be held on February 16, 2002. Subsequently, the exchange vide their letter dated March 28, 2002 informed that the said meeting proposed to be held on February 16, 2002 could not be held and the council met on March 26, 2002 and took the following decisions :-

- (a) A committee was constituted consisting of the following public representatives to enquire into complaints against the Executive Directors :
  - (i) Shri M. N Ray
  - (ii) Shri G.K Upadhyaya
  - (iii) Shri Samson Maharana
- (b) The Board of Trustees of the Members Welfare Trust could not be reconstituted for want of adequate representation by members.
- (c) The following members have failed to pay dues owed to the Members Welfare Trust :
  - (i) Shri Anjani Kumar Singh
  - (ii) Shri Babulal Sharma
  - (iii) Shri Arun Kumar Girdhar
  - (iv) Shri S. Kedar Swamy Patra
  - (v) Shri Dharmendra Prasad Singh

The council also decided to issue notice of suspension to the above members in accordance with the rules and bye laws of the exchange.

- (d) The council authorised Shri Thomas Mathew to consult an advocate to examine the feasibility of initiating criminal proceedings against the beneficiaries of loans granted by the Members Welfare Trust.

3.2 SEBI vide its letter dated April 30, 2002 forwarded a copy of the inquiry report dated October 22, 2001 and directed BhSE to take action against the following members as specified hereunder :

- (i) Shri Anjani Kumar Singh – suspension for 2 years
- (ii) Shri Babulal Sharma – suspension for 2 years
- (iii) Shri Manoj Thakar - suspension for 1 year
- (iv) Shri Dharmendra Prasad Singh - suspension for 1 year

They were also directed to issue show cause notices to the said members and also directed that the show cause notices should mention the penalty proposed to be imposed and that the members should be granted a personal hearing. The stock exchange was also advised that in the light of the personal hearing, if they are of the opinion that the directive of SEBI needs to be modified, they may take up the matter with SEBI.

No reply was forthcoming from BhSE to the letters dated January 29, 2002 and April 30, 2002 and therefore, vide letter dated August 5, 2002 addressed to the Executive Director and Council of Management, SEBI directed them to comply with the directions mentioned in the said letters and submit their report within 2 weeks

from date of receipt of the letter. They were also directed to submit the report of the committee constituted to enquire into complaints against the Executive Director within 2 weeks from date of receipt of the letter. The stock exchange vide its letter dated August 22, 2002 informed that a meeting of the council of management will be held on August 28, 2002 to take up matters relating to compliance of directions given in the letters dated January 29, 2002 and April 30, 2002.

4.0 While the above matter was pending, SEBI received complaints from Shri Kedar Swamy Patra, member of BhSE and Shri M. N Ray, public representative alleging financial fraud and irregularities in the exchange. Further, SEBI came to know through newspaper reports that certain members of the exchange had been arrested and imprisoned for murder and that there were several irregularities taking place in the stock exchange. In the light of the said complaint and media reports, SEBI undertook an inspection of the BhSE during the period August 29 to August 30, 2002. The inspecting team made the following observations:

- (i) BhSE has no turnover ; last trading on the floor of the exchange took place on May 25, 2000. The exchange has also no trading in their subsidiary i.e Bhubaneswar Shares and Securities Ltd on BSE and there is negligible turnover on the ISS Segment. Presently, only 68 companies are listed with the exchange, the last listing being in May 2000. Thus, the exchange is not performing the role of providing a platform for equity trading; on the other hand, the trading in equities has shifted from BhSE to NSE and the trading terminals of NSE are providing

facilities for equity trading to investors originally serviced by BhSE.

- (ii) The annual accounts for the year 2000-01 is yet to be adopted and the annual accounts for the year 2001-02 is yet to be finalised. The annual accounts for the year 2000-01 was placed before the Annual General Meeting held on September 29, 2001 but the same was not adopted due to the demand of the members to audit the books of account of the members Welfare Trust for the years 1997-98, 1998-99, 1999-00 and 2000-01. An auditor appointed to audit the books of account of the Welfare Trust submitted their report to the exchange on July 12, 2002. After perusal of the report, the council decided to request the auditors to review the work.
- (iii) BhSE had an excess of income over expenditure to a tune of only Rs. 29 lacs, whereas, the exchange has Rs. 4.94 crore as cash and bank balance which generates most of its income in the form of interest. Therefore, it appears that the exchange is at present surviving on the interest income earned through the deposits.
- (iv) There is conflict between various functionaries of the exchange. The Executive Director and the Secretary of the exchange do not have a cordial relationship with the Council of Management and many of the members of the council are seen to be acting against the Executive Director and Secretary. The exchange officials are not devoting sufficient time and efforts towards the day to day functions of the exchange. In this regard, as an instance of the conflict of interest, it was noted during the inspection that the council of management in its meeting on July 17, 2002 asked the public

representative Shri M.N Ray to prepare draft charges against the Executive Director and Secretary for their poor performance, professional misconduct, dereliction of duties and misappropriation of funds of the stock exchange. However, Shri Ray instead of submitting the draft charges to the council of management issued a show cause notice to the Executive Director and Secretary wherein, he described himself as Chairman of the exchange.

- (v) The Committee constituted to enquire into the charges against the Executive Director was constituted on March 26, 2002 and later 2 more members were added on July 17, 2002. Although, the committee has met 3 times, they have failed to submit their report within 6 months as directed by SEBI. Till date, the committee has not submitted their report to SEBI.
- (vi) With regard to irregularities in the disbursal of loans from the MWT, it was observed that the MWT had delivered 16,200 shares of Reliance Industries Ltd to one broker on NSE - M/s Indian Finance Guarantee Ltd (IFGL). These shares were sold @ Rs. 367/- per share. The details of proceeds of the said transactions are as under :-

Sr. No	Name of the loanees	Number of shares	Rate	Amount (Rs.)
1	Pradeep Investment	5350	367	1963450
2	Kumar & co	1900	367	697300
3	A.K Financial & Co	4600	367	1688200
4	Giridhar & Co	2000	367	734000
5	D.P Singh & Co.	2350	367	862450
	<b>Total</b>	<b>16200</b>		<b>5945400</b>

BhSE received only Rs. 46,60,624 out of the total sale proceeds of 59,45,400 and an amount of Rs. 12,84,776 is due from IFGL. However, BhSE has no documents pertaining to the sale of these shares and no contract notes were found on scrutiny of the records.

- (vii) A house building advance of Rs. 10 lacs has been sanctioned to the Secretary and the Executive Director. However, the said loans have not been secured by mortgage of properties. In addition to the above, the entire amount of the loan was disbursed to the Secretary even before construction of the house. Further, the secretary also applied for a housing loan from the Union Bank of India who requested the ED to transfer the housing loan of the Secretary to the Bank.
- (viii) Several office bearers of the exchange including certain members of the Council of Management have made the allegation that Shri M.N Ray, public representative has exceeded his authority. In this regard, the inspection team observed the following :-
  - (a) Shri M.N Ray had written a letter to the ED of the exchange to release Rs. 70,000 for booking of air tickets for proposed visits to Mumbai and New Delhi. However, the Council of Management did not release the money.
  - (b) The Council of Management had asked Shri M. N Ray to prepare draft charges against the E.D and Secretary of the Stock Exchange but, Shri Ray instead of submitting the draft charges to the Council



of Management, issued a show cause notice to the E.D and the Secretary. In the said show cause notice, he also used the designation of Chairman of the Exchange.

(c) Shri Ray issued letters to the E.D asking for information such as cash flow statement of the exchange from September 2001 to February 2002 and such other information.

(ix) There is a proposal to construct a new building for the exchange. The land has already been acquired and the exchange has constituted a building committee to co-ordinate and oversee the construction. The said committee in its meeting dated June 11, 2002 proposed to the council of management to approve expenditure of Rs. 60 lacs towards the new building. The substantial investment in a new building may adversely affect the cash and bank balances with the exchange and thereby, considerably reduce the interest earnings on which the exchange now survives.

5.0 In view of the failure of BhSE to carry out the directives of SEBI and in the light of the observations made by the inspecting team, it appeared that the Council of Management of the exchange has failed to effectively discharge its duties and therefore, SEBI issued a show cause notice dated September 24, 2002 advising them to show cause why appropriate action including supersession should not be taken against them.

5.1 The Council of Management of BhSE submitted their reply vide letter dated October 8, 2002. In their reply, they have stated as follows :-

1966/03-4

- (i) The committee formed to enquire into complaints against the Executive Director has submitted its report and the same will be forwarded to SEBI after the council of management gives approval to the same.
- (ii) The constitution of the members welfare trust has been amended suitably and at present there are five trustees out of which three are non elected directors. The trust has also stopped granting loans to members of the exchange since December 2001.
- (iii) Members having outstanding loans from the Members Welfare Trust including Shri Babulal Sharma, Shri Anjani Kumar Singh and Shri Manoj Thakkar are no more office bearers of the exchange, nor are they holding any post in any of the segments where the exchange is acting as a broker.
- (iv) The following penalties have been imposed on some of the members who have taken loan from the Members Welfare Trust.
  - 1. Shri Babulal Sharma – Expelled from the exchange
  - 2. Shri Anjani Kumar Singh – Expelled from the exchange
  - 3. Shri S. Kedar Swamy Patra – Suspended from the membership rights
  - 4. Shri Dharmendra P. Singh – Matter is sub-judice
- (v) Necessary legal steps for recovery of outstanding loans have been taken and five persons including the erstwhile executive director and secretary of the stock exchange have been arrested by the state police for financial irregularities.

- (vi) Members having outstanding loans have been barred from conducting trading in any of the segments of the exchange.
- (vii) The Council of Management in its meeting held on March 1, 2002 had decided not to allow withdrawal of BMC and security deposit and adjustment of the same against outstanding dues. The Council of Management has also decided to stop granting loans to the Members Welfare Trust.
- (viii) With regard to absence of turnover, the council submitted that the nature of trading has become cyclical nationally and internationally and they do not have any control over the volume of trading and this cannot be construed as a ground for supersession.
- (ix) With regard to the annual accounts for the year 2000-01, the council submitted that the same could not be adopted because of the fact that there were inherent irregularities in the accounts of the MWT members welfare trust. The accounts of the MWT for the years 1997-98, 1998-99 and 1999-00 and 2000-01 have been accepted by the Council of Management in its meeting dated October 1, 2002 and the same are being placed in the annual general meeting to be held on November 9, 2002. Subsequent to the adoption of the accounts of the exchange for the year 2000-01, the accounts for the years 2001-02 will be placed to the council for approval.
- (x) The conflict between the functionaries of the exchange was as a result of siphoning / abetting siphoning of funds of the exchange by office bearers and officers of the exchange. As a result of the Executive Director and Secretary being arrested and thereafter suspended, this conflict has come to nought.

- (xi) With respect to the sale of securities in favour of IFGL, the council is initiating both civil and criminal action.
- (xii) With regard to the housing loan, Shri Sanjay Mahapatra, Secretary (under suspension) has repaid his housing loan and the exchange is considering legal steps for recovery of housing loan availed by Shri Jay Sadany, Executive Director (under suspension).

5.2 In view of the above, the Council of Management requested SEBI not to take any action including supersession of the council of management. As per the request of the Council of Management of the Stock Exchange, an opportunity to be heard before the Chairman was granted to them on November 20, 2002. During the hearing, the Council of Management of BhSE was represented by M/s L N Patnaik, S K Jhingan and M N Ray, all directors of BhSE. Shri M N Ray is also the public representative on the Council. In the course of the hearing, the directors of the exchange submitted that they have taken effective steps to exclude the persons responsible for the irregularities at the stock exchange from responsible positions and a few of them have even been arrested by the State Police. They requested that they may be given another chance to turnaround the management of the stock exchange. They also referred to the misdeeds of the earlier council of management and stated that they would like to have some more time to take action against the persons responsible for the irregularities in the BhSE.

6.0 I have carefully considered the facts of the matter, the reply submitted by the Council of Management of BhSE and the submissions made by their representatives before me in the course of personal hearing before me.

7.0 I find that BhSE has failed to implement the directives of SEBI issued under Rule 11 of the SCRR and communicated vide letters dated January 29, 2002, April 30, 2002. The report of the Committee constituted by the Council of Management to enquire into the allegations against the Executive Director is yet to be submitted to SEBI although it was stipulated in SEBI's letter dated August 5, 2002 that the same should be submitted within 2 weeks from date of receipt of the said letter.

7.1 I find that conflict between various functionaries of the stock exchange still exists and that the Council of Management has not regained credibility. The Executive Director and Secretary of the Stock Exchange have been arrested by the State Police and consequently suspended by the Stock Exchange. In order to replace them, the Council of Management has appointed one Shri Bhagyadhar Behera as Secretary and entrusted M/s Gadadhar Mishra and Tapan Ranjan, Assistant Managers with the task of running the day to day affairs of the exchange under the supervision of a sub-committee consisting of the Chairman and two public representatives. SEBI has received complaints against the secretary, Shri Bhagyadhar Behera from members of the exchange also from one of the public representatives on the sub-committee, Shri M N Ray. It has also been brought to the notice of SEBI that the Hon'ble High Court of Orissa has passed severe strictures against Shri M N Ray. Therefore, it cannot be said that cordial relation among the functionaries of the stock exchange and credibility of the members of the Council of Management has been restored.

7.2 I find that the stock exchange has failed to adopt the accounts for the years 2000-01 and 2001-02. The failure to adopt the accounts indicates financial mis-management. The explanation submitted by the exchange in this regard that the accounts shall be adopted at the Annual General Meeting to be held on

November 9, 2002 has not been substantiated by action since no statements in this regard has been forwarded to SEBI. Further, accounts for the year 2001-02 are yet to be adopted.

7.3 I find that no effective steps have been taken by the Council of Management with regard to the irregularities in payments made to M/s Indian Finance Guarantee Ltd. The explanation of the council that the matter has been taken up with IFGL for making good the shortfall and that the council is initiating both civil and criminal action, is not satisfactory. The irregularities were noticed in the year 1999 and were also mentioned in the report of the inquiry officer submitted on October 22, 2001. However, BhSE is yet to take any effective action in this regard.

7.4 I find that during the course of hearing, the submissions made by the representatives indicated that they only wished to take action against their predecessors and that they were not inclined to follow the directives of SEBI. Moreover, two of the representatives who appeared before me were found to be lacking in credibility. As mentioned hereinbefore, strictures have been passed by the High Court of Orissa as per the report of the inquiry officer, against Shri M.N Ray and Shri S.K Jhingan is one of the defaulters in respect of the loan availed from MWT.

8.0 In view of the above facts, I am convinced that the Council of Management of Bhubaneswar Stock Exchange has failed to ensure proper governance and implementation of the provisions of the SCRA and SEBI directives and to ensure proper financial integrity in the functioning of the exchange. As a result of this, confidence of investors in the functioning of the exchange has been impaired.

- 9.0 Due opportunity was given to the Council of Management of Bhubaneswar Stock Exchange to show cause as to why it should not be superseded. The reply given by the Council of Management is not found to be satisfactory. Therefore, I am of the opinion that it is essential that immediate measures are taken to ensure safety and integrity of the market and to restore the confidence of investors in the functioning of the Stock Exchange.
- 10.0 SEBI is mandated to ensure that the effective steps are taken to protect the safety and integrity of the market and to protect the interest of the investors. Therefore, it is necessary that the persons who have failed to take effective action need to be excluded from governance of the exchange and an independent and impartial person is appointed.
- 11.0 In view of the above and in exercise of the powers conferred on me under Section 11 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 read with Government of India Notification No. S.O.573 dated July 30, 1993 and Section 4 (3) of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, I hereby supersede the Council of Management of Bhubaneswar Stock Exchange with effect from January 3, 2003 for a period of one year and appoint Shri. Jai Prakash Verma as an administrator to exercise and perform all the powers and duties of the Council of Management. Shri. Jai Prakash Verma may take the assistance of such persons as he deems necessary in discharge of his duties as administrator.

[File No. SEBI/LE/23/03]

G. N. BAJPAJ, Chairman